



VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 876)

Name of Candidate	RHEECHA RATNAM		
Medium Eng./Hindi	HINDI	Registration Number	4680
Center	RAJENDRA NAGAR	Date	30/09/17

INDEX TABLE			INSTRUCTIONS
Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained	
1	12.5		<ol style="list-style-type: none">Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code). उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।There are TWENTY questions printed in ENGLISH & HINDI इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।All questions are compulsory. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।The number of marks carried by a question/part is indicated against it. प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one. प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।Word limit in questions, if specified, should be adhered to. प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off. उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।
2	12.5		
3	12.5		
4	12.5		
5	12.5		
6	12.5		
7	12.5		
8	12.5		
9	12.5		
10	12.5		
11	12.5		
12	12.5		
13	12.5		
14	12.5		
15	12.5		
16	12.5		
17	12.5		
18	12.5		
19	12.5		
20	12.5		

Total Marks Obtained:

Remarks:

75, 3rd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Near Axis Bank, New Delhi – 110060

103, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi – 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks.

12.5X20=250

1. While India has taken a number of steps in order to substantially improve its ranking in the World Bank's 'Ease of Doing Business' Index, it needs to take further action in this regard. Elaborate. Also analyse the utility of these rankings vis-a-vis India's objective of facilitating a sound entrepreneurial environment.

जहाँ, भारत ने विश्व बैंक के 'इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (व्यापार करने की सुगमता) सूचकांक में अपनी रैंकिंग में सार्थक सुधार करने हेतु कई कदम उठाए हैं, वहीं भारत को इस संबंध में आगे और अधिक कार्यवाही करने की आवश्यकता है। सविस्तार वर्णन कीजिए। साथ ही सुदृढ़ उद्यमिता वातावरण प्रदान करने के भारत के उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में ऐसी रैंकिंग की उपयोगिता का भी विश्लेषण कीजिए।

→ विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित 'इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' सूचकांक, किसी देश में व्यापार करने की सुगमता दर्शाता है।

• 'इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' सूचकांक, 2017 के अनुसार, भारत 130वें स्थान पर है।

* 'इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' सूचकांक के धरोकर

- | | |
|----------------------------|---|
| (i) व्यापार शुरू करना | (vi) विवाद समाधान |
| (ii) कॉन्ट्रैक्ट लागू करना | (vii) क्रेडिट प्राप्त करना |
| (iii) विद्युत पाना | (viii) वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजना |
| (iv) संपत्ति का पंजीकरण | |
| (v) कर भुगतान | |

* भारत द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम :-

(i) व्यापार सुरक्षा कानून :- केंद्र सरकार द्वारा ई-बीपी (e-bi) पोटल की शुरुआत, जहाँ विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन व एकल खिड़की उपलब्ध कराई गई है। ईवेर इंशुरेंस के माध्यम से विदेशी निवेशकों की लक्ष्यता।

(ii) विवाद समाधान -

- इनसोलवेंसी व बैंकर्स की कोठ चारिता कानून (IBC) से जुड़े विवादों का समाधान निर्धारित समय सीमा में कोठा।

(iii) वस्तुओं को बाजार के आर-पार भेजना

- WTO के व्यापार सुगमता समझौते (TFA) को भारत द्वारा लागू किया गया, जो, बफरबॉर्ड या विभिन्न प्रक्रियाओं-कस्टम इत्यादि को सरल बनाएगा

(iv) कर प्रक्रिया सरल बनाने हेतु, सकारात्मक वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू की गई है।

* भारत को व्यापार सुव्यवस्था हेतु अन्य कदम उठाने की आवश्यकता है :-

- (i) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को त्वरित व सुव्यवस्थित बनाना।
- (ii) श्रम सुधारों को लागू करना - उदाहरण श्रम स्थान द्वारा श्रम सुधार।
- (iii) विभिन्न कानूनों में परिवर्तन करना - उदाहरण :- कॉम्पैक्ट लॉ को लागू करना

• डब्ल्यू ऑफ इंडिया बिजनेस सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में किसी देश में, व्यापार कानून की सरलता दर्शाता है।

• यह दर्शाता है कि, किसी विश्वी निवेशक के लिए, किसी देश में निवेश करना या व्यवसाय कानून की प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न चरणों में, कितना समय लगता है। उदाहरण :- विद्युत पान में कितना समय।

• भारत, जो कि वैश्विक स्तर पर बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है, उसे अपने देश में, निवेशक सहयोगी माहौल बनाना अनिवार्य होगा।

• नीति आयोग द्वारा विश्व बैंक के साथ मिलकर, राष्ट्रों के लिए 'डब्ल्यू ऑफ इंडिया' बिजनेस रेकिंग जारी करना, इस विद्या में सकारात्मक प्रयास है।

2. In wake of the agrarian crisis that the country is witnessing, discuss the need for adopting an income-centric approach in preference to a production-centric one as the basis of agricultural policy. In this context, also highlight the steps that should be taken to achieve the goal of doubling the income of farmers by 2021-22 and the challenges that exist.

देश द्वारा सामना किए जा रहे कृषि संकट के आलोक में, कृषि नीति के आधार के रूप में उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर आय-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में, 2021-22 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, उनके साथ-साथ विद्यमान चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिए।

हाल के दिनों में, भारत के विभिन्न राज्यों में कृषकों का प्रदर्शन - महत्वपूर्ण, महाराष्ट्र, चर्चा में रहा है।

• कृषक, अच्छी उपज के बावजूद, अपनी उत्पादों का बेहतर मूल्य पाने में असफल रहे हैं।

- भारत में लगभग 48% (किसान) श्रमबल, कृषि क्षेत्र में नियोजित है, जिसका पीडीपी में योगदान 17% है। (अधिक संवेदन)

स्पष्ट है कि, श्रमबल का एक बड़ा भाग, निम्न उत्पादकता क्षेत्र में लगा है, साथ ही 12% कृषक लघु व सीमांत हैं।

- भारत में पूर्व में अपनाई गई कृषि नीति का लक्ष्य 'उपज में वृद्धि' द्वारा व्यापक सुरक्षा प्राप्त करना था, लेकिन अब यह आवश्यक है कि भारत में कृषकों का आय में वृद्धि हो।

कदम उठाए जाए।

- नीति आयोग के त्रि-वर्षीय उपपत्र में, 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।

* केंद्र व सरकार द्वारा कृषकों की आय दोगुना करने हेतु, अशोक दलवर्द्ध समिति का गठन किया गया।

- अशोक दलवर्द्ध समिति : सुझाव

- (i) कृषि विपणन को समर्थनी सूची में शामिल करना।
- (ii) कृषि उत्पाद आपूर्ति शृंखला में निजी क्षेत्र को प्रवेश।
- (iii) FPO (Farmer Producer Organization) के गठन को प्रोत्साहन।

* भारत में, कृषकों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न चुनौतियों का वर्णन, आर्थिक संवर्द्धन 2016-17 में किया गया है।

चुनौती	वर्तमान स्थिति	उठाए जाने वाले कदम (अवसर)
(i) कीमत संवेदी	- किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में असफल। कृषि विपणन में मध्यस्थों की भूमिका	- मॉडल APMC अधिनियम लागू करने की आवश्यकता - e-NAM के प्रयोग को प्रोत्साहन - कृषि विपणन में निजी क्षेत्र को

- * सरकार द्वारा इस हेतु उठाए गए कदम -
 - (i) माडल APMC अधिनियम बनाना, तथा शायों को इसे अपनाते हेतु कहना
 - (ii) e-NAM (e-नाम), द्वारा, कृषकों के उत्पादों के ऑनलाइन बिक्री, माफ उच्च बेहतर उत्पाद मूल्य प्राप्त करने का अवसर दिया जा रहा है।
 - (iii) निम्नी कंपनियों - इमप्लेंट, क्लिबॉके को, कृषि उत्पादों के आपूर्ति शृंखला में शामिल करना।

* निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता व संबंधित चुनौतियां :-

क्षेत्र	कदम उठाने की आवश्यकता	चुनौतियां
1. उत्पादन	कम उत्पादन लाभ व अधिक उत्पादन पर ध्यान - सुफा स्वास्थ्य कार्ड	कृषि अनुपयोग, उर्वरक, बीजों के प्रयोग का सुनिश्चित करना।
2. बाजार जोखिम से किसानों को बचाना	संविदा कृषि को प्रोत्साहन। साकारा न्याय न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रयोग।	संविदा कृषि, कृषि के कार्योपेक्षी कारण को बचाना देना। CAG के सुझाव।
3. आय सुरक्षा	फसल बीमा योजना का विस्तार।	बीमा योजना को प्रसारित करना है।

भारत को अन्न केंद्रित कृषि से बाहर निकालना होगा, व कृषकों की आय में हासिल हेतु, सरकार माफ उठाए जा रहे कदम एकतात्मक है।

3. It is argued that India's fiscal centre of gravity has rapidly shifted from the Centre to the States. Analyse the statement in context of the debate on fiscal discipline. Also, enumerate the key recommendations of the N.K. Singh panel on Fiscal Responsibility and Budget Management Act.

यह तर्क दिया जाता है कि भारत का राजकोषीय गुरुत्वाकर्षण का केंद्र तेजी से केन्द्र से राज्यों की ओर स्थानांतरित हुआ है। राजकोषीय अनुशासन पर वाद-विवाद के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पर एन. के. सिंह पैनल की प्रमुख अनुशंसाओं को सूचीबद्ध कीजिए।

- राजकोषीय अनुशासन के अंतर्गत सरकार अपने आय व व्यय को संतुलित करने का प्रयास करती है; ताकि उसका राजकोषीय घाटा, ऋण/बीडीपी अनुपात, राज्य घाटा इत्यादि अधिक न हो।
- राजकोषीय घाटा, किसी देश की राजकोषीय प्रबंधन क्षमता को दर्शाता है साथ ही यह दर्शाता है कि, देश राजकोषीय सतता की नीति का पालन कर रहे हैं, या नहीं।
- भारत में, केंद्र ने 2003 में, राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम (FRBM) अपनाया था, जिसका लक्ष्य, राजकोषीय घाटे का $\approx 3\%$ करना व राज्य घाटे को शून्य करना था। हालांकि, यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।
- राष्ट्रीय स्तर भी, अपने राजकोषीय प्रबंधन हेतु, राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम (FRM) को अपनाया गया।

* FIRL अधिनियम अपनाने के बाद, राज्यों के राष्ट्रकोषीय प्रदर्शन में व्यापक सुधार हुआ :-

(i) राज्यों का औसत राष्ट्रकोषीय धारा < 3%.

(ii) राज्यों का औसत ऋण/जीडीपी < 22%.

• हालांकि, हाल के दिनों में राज्यों के राष्ट्रकोषीय धारे में वृद्धि हो रही है, जिसका कारण है :-

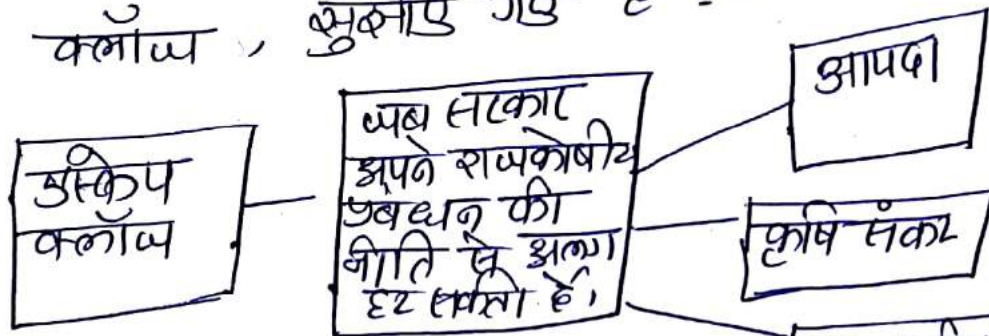
(i) 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करना।

(ii) उद्योग योजना के अंतर्गत विकास को ऋण सहायता।

• केंद्र ने राज्यों को, उनके राष्ट्रकोषीय धारे के प्रबंधन हेतु, पूर्व में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CPS) के अंतर्गत अनुशंसा लागू करने का विकल्प में वृद्धि की शर्तों के अंतर्गत कदम उठाए हैं।

* हाल ही में, उन के सिंह समिति ने, भारत के लिए नए राष्ट्रकोषीय प्रबंधन उपाय सुझाए हैं, जो निम्नलिखित हैं :-

- (i) भारत को FRBM को पढाए नउ, राज्यकोषीय व तदनु संबंधन अधिनियम को अपनाना चाहेए।
- (ii) 2022-23 तक, केंद्र का राज्यकोषीय धारा = 2.5% केंद्र की सिफारिश।
- (iii) 2022-23 तक, भारत का तदनु (पीडीपी) = 60% (पीडीपी का)
- (iv) विशेष परिस्थितियों में, राज्यकोषीय संबंधन के संबंध में पुस्केप कमाए, सुझाए गए हैं :-



(v) स्वतंत्र, राज्यकोषीय विनियामक बोर्ड के गठन का सुझाव, जो केंद्र व राज्यों की राज्यकोषीय नीतियों का विनियामक होगा। पूर्व में, राज्यों द्वारा, अपने राज्यकोषीय धाटे का संबंधन, केंद्र की अपेक्षा अधिन अर्द्ध तरीके से किया गया है, हालांकि इसमें केंद्र का सहयोग, महत्वपूर्ण रहा है।

अभ्यास का। निवेशकों को आकर्षित करने में सफल हो सकता है।

4. Strategic sale of state-run firms is a prudent step to deal with the challenges being faced by the public sector enterprises in India. Comment. Also enumerate other measures that can be taken in light of NITI Aayog's suggestions in this regard.

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य-संचालित उद्यमों की रणनीतिक बिक्री एक विवेकपूर्ण कदम है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही इस संबंध में नीति आयोग के सुझावों के प्रकाश में उठाए जा सकने वाले अन्य उपायों को भी सूचीबद्ध कीजिए।

रणनीतिक बिक्री के अंतर्गत 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के 50% से अधिक शेयरों की बिक्री का आता है, तथा इसका संबंध निजी क्षेत्र को सौंपा जाता है।

- केंद्र सरकार, PSU की रणनीतिक बिक्री, निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु करती है-
 - (i) PSU के प्रबंधन में क्कता लाना
 - (ii) सरकार के शपस्य व्यय में क्मी लाना।
 - (iii) निजी क्षेत्र के सफल नीतियों का PSU को लाभ कमाने वाली क्पनी में परिवर्तित काना।
- हाल ही में केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश की घोषणा की है।

— एयर इंडिया, 50,000 कोड़ से अधिक के त्रहण घाटे पर चल रही है;

• सरकार, विनिवेश द्वारा PSU में अपने स्वामित्व को समाप्त करती हैं तथा निजी क्षेत्र को कंपनी का प्रबंधन सौंपती हैं।

* PSUs द्वारा लागत को घा रही, प्रमुख चुर्गेतियां निम्नलिखित हैं :-

(i) PSU, सर्पिष्यनिक उद्यम, पिन्का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है; फलस्वरूप कंपनियां प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाती हैं।

(ii) PSU, अपने निधिचयन हेतु सरकार पर निर्भर होते हैं, पिन्के कारण इनका निधि स्रोत सीमित रहता है;

(iii) PSUs की प्रबंधन क्षमता में वक्षता का अभाव, पिन्के कारण वे धीरे में रहते हैं।

— हाल के वर्षों में, जब सरकार अपनी, शक्यतायुक्त अनुशासन की नीति के अंतर्गत अपना धारा कप्त करती चली है, PSU के विनिवेश द्वारा

इस काम को का प्रयास किया जा रहा है

* विनिवेश : आलोचना :-

(i) सांख्यिकीक नियंत्रण, पतन के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जिसकी अपेक्षा निजी क्षेत्र से नहीं की जा सकती है।

उदाहरण :- एयर इंडिया, कम लाभ वाले एयर मार्गों पर भी उड़ान भरती है।

(ii) आमियों द्वारा PSU के बिक्री का विरोध किया जाता है; क्योंकि इससे उनकी नौकरी पर खतरा बढ़ जाता है।

* नीति आयोग द्वारा विनिवेश के संबंध में दिए गए सुझाव :-

(i) घाटे में चल रही कंपनियों की बिक्री निजी क्षेत्र को करने की आवश्यकता।

(ii) अन्य PSU को, शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करना।

(iii) कुछ कंपनियों के विनिवेश हेतु, कानून में संशोधन की आवश्यकता है।

हाल के वर्षों में, यहां निजी क्षेत्र का विकास, अर्थव्यवस्था के उत्थेक क्षेत्र में बढ़ रहा है, सरकार अपनी भूमिका 'सेवा प्रदाता' को का रही है, जो भविष्य में सफल काम साबित हो सकता है।

5. Shell companies in India are neither legally defined nor properly understood. Analyse in the light of recent developments, prevalent understanding and steps required to effectively deal with shell companies.

भारत में शेल कंपनियों न तो कानूनी रूप से परिभाषित हैं और न ही उनके विषय में उचित समझ है। हाल के घटनाक्रमों, व्याप्त (प्रचलित) समझ और शेल कंपनियों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु आवश्यक कदमों के आलोक में विश्लेषण कीजिए।

→ हाल ही प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि, 5.5 लाख शेल कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।
- सेबी ने भी, 331 शेल कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही की है।

* शेल कंपनियां क्या हैं?

→ भारत में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शेल कंपनियों की परिभाषा नहीं की गई है।

• हालांकि सामान्य अर्थ में शेल कंपनियों, वैसी कंपनियां होती हैं, जिनका न तो अपना कोई व्यवसाय होता है; व न अपनी संपत्ति होती है।

शेल कंपनियां, मुख्यतः

मनी लाउंड्रिंग का कार्य करती हैं, जिसके कारण ये अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है।

- विमुद्रीकरण पश्चात्, RBI की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 99% 500 व 1000 रुपये के नोट, बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत वापस आ गए हैं।
 - इस प्रक्रिया में बैंक कंपनियों ने व्यापक भूमिका निभाई है, तथा कोल धन को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल कराया है।
- * बैंक कंपनियों से निपटने हेतु उठाए गए कदम :-

- (i) आयकर विभाग व अन्य विभागों द्वारा, ऑपरेशन क्लोन मनी के अंतर्गत बैंक कंपनियों की बालिविधियों की मान्यता को रद्द कर दिया है।
- (ii) बिजु डेटा के माध्यम से बैंक कंपनियों को पहचानने का कार्य किया जा रहा है।

* भारत में शेल कंपनियों से निपटने में चुनौतियां :-

(i) आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं, फलस्वरूप इनकी पहचान करने हेतु, कोई एक मानक नहीं है।

(ii) हाल ही में सेबी द्वारा, शैल बाजार निवेश से जुड़ी कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, के कारण अन्य कंपनियों (जो शेल कंपनियां नहीं) में भी भय व्याप्त हो गया है।

• भारत में शेल कंपनियों से निपटने हेतु निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है :-

(i) उन्हें परिभाषित करना तथा, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत उनसे जुड़े फंड के प्रावधानों को सम्मिलित करना।

काले धन से निपटने हेतु, लक्सा, काप, JTA राबन, विमुक्ति काल व शेल कंपनियों पर धारा, अकालमक कदम है।

6. If a larger population in India is to be involved in the economy in a big way, Small and Medium Enterprises (SMEs) are key. Elaborate. Also discuss the challenges faced by the SME sector in India and give an account of the measures taken by the government to deal with these.

यदि भारत में एक बड़ी आबादी को अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर सम्मिलित करना है, तो लघु और मध्यम उद्यम (SMEs) महत्वपूर्ण हैं। सविस्तार वर्णन कीजिए। इसके साथ ही, भारत में SME क्षेत्रक द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए और इनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण भी प्रदान कीजिए।

भारत में लघु व मध्यम उद्योग (SME) का कुल विनिर्माण जीडीपी में 31.1% का योगदान है। [आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19]

* भारत में SME क्षेत्र निम्नलिखित रूप से सहायक है :-

- (i) यह श्रमबल के बड़े भाग को रोजगार प्रदान करता है।
- (ii) विनिर्माण प्रक्रिया में फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंक का कार्य करता है; जिसका लाभ प्राथमिक क्षेत्रक (कृषि) को प्राप्त होता है।
- (iii) SME क्षेत्र, भारत में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन (उद्योग) को कम करने में सहायक है।
- (iv) यह राष्ट्रीय आय का समुचित

किरण सुनिश्चित करता है।

स्पष्ट है कि, भारत के
आर्थिक विकास में SME क्षेत्र की
महत्वपूर्ण भूमिका है।

* हाल के वर्षों में SME क्षेत्र द्वारा
स्वामना की जा रही चुनौतियाँ :-

(i) बैंक तटन प्रॉब्लम :- आर्थिक संकट
2016-17 के झुला, SME क्षेत्र को
जाम होने वाले बैंक तटन में कम
आई है।

— इसके कारण कस क्षेत्र में औद्योगिक
बालिविधियाँ व्यापक रूप से प्रभावित हुईं।

(ii) अन्य स्रोतों से - कैंसर बाजार, कैंसर
कंपिल जम काल में SME क्षेत्र
असमर्थ है।

(iii) विमुद्रीकरण का प्रभाव SME,
आर्थिक बालिविधियों पर पड़ा है, क्योंकि
यह नकद आधारित क्षेत्र रहा है।

(iv) हाल ही में लागू वस्तु व सेवा कर
(GST), से SME क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

• GST के, अंतर्गत का नहीं चुकाने वाली कंपनियों से खरीदे गए भागों पर उत्पादक कंपनी को का देना होगा, जिससे SME क्षेत्र, और वाले वर्षों में घाटे में जा सकता है।

* सरकार द्वारा SME क्षेत्र को डेवलाप करने हेतु उठाए गए कदम :-

(i) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत SME क्षेत्र को औपचारिक संस्थानों में काम ब्याप पर तद्वत उद्वेगकों

(ii) प्राथमिकता उदात्त क्षेत्रों (PSL) को तद्वत प्रदान करने संबंधी दिशा-निर्देशों में RBI ने SME क्षेत्र के लिए 7.5% तद्वत राशि, अनिवार्य किया है, (कुल PSL तद्वत का)

(iii) प्रधानमंत्री रोजगार डेवलाप योजना द्वारा SME क्षेत्र में, रोजगार को डेवलाप

SME क्षेत्र, भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख अयव है, तथा इसको द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के लिए कदम द्वारा आवेष्ट में और कदम उठाए जाएंगे।

7. What are the reasons for the growing informalization of industrial labour in India? Discuss the issues associated with the phenomenon and reforms required to deal with them.

भारत में औद्योगिक श्रम के बढ़ते अनौपचारिकरण के क्या कारण हैं? इस परिघटना से जुड़े मुद्दों और उनसे निपटने हेतु आवश्यक सुधारों पर चर्चा कीजिए।

आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, 1989-2010 के मध्य सृजित हुए 10.5 मिलियन रोजगारों में सिर्फ 35% रोजगार औपचारिक क्षेत्र में सृजित हुए हैं।

• विनिर्माण क्षेत्र में, उदरिकरण पश्चात् सृजित 70% रोजगार अनौपचारिक हैं।

* भारत में विनिर्माण क्षेत्र के अनौपचारिकरण के कारण :-

(i) भारत में विनिर्माण क्षेत्र में, सूची बहक उद्योगों की प्रमुखता और फगात्परूप श्रम बहक उद्योग-वस्त्र, चमड़ा कृषिदि का विकास नहीं हुआ।

- इसके कारण लोगों को औपचारिक नौकरियां प्राप्त करने में समस्या है।

(ii) रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल :- इस सबद का उद्योग आर्थिक सर्वेक्षण में

विनिर्माण उद्योग से जुड़े विनियमन को ढीले के हेतु किया गया था, जिसके कारण भारत में अर्द्ध जाक सृजित नहीं हो पा रहे हैं :-

(i) EPFO में अनिवार्य योगदान की अति ।

(ii) श्रम सुधारों में सुरती, जिसके कारण उद्योगिक परचात । भारत में संविदा श्रमिकों की संख्या में उछि हुई है। उदाहरण :- उद्योगों ले श्रमिकों को निशालना, उद्योगों को बंद करना ।

(iv) कृषि की कमी :- भारत में सिर्फ 5% श्रमिक कृषि में हैं; जबकि अन्य देशों - जर्मनी में यह अनुपात 90% है।

* भारत में विनिर्माण क्षेत्र के औपचारिकरण से जुड़े मुद्दे :-

(i) श्रम बहन उद्योगों का स्थान -
- कपड़ा व चमड़ा उद्योगों की उग अक्षे में स्थापित करने की आवश्यकता है,

जहाँ, मजदूरी कम हो, किराया कम हो।
(ii) भारत की आर्थिक संवर्द्ध के दौर (2000-2010) को, शिथिलगति (slow growth) कहा जाता है; क्योंकि इस दौर में पर्याप्त अर्थ व्याप्त नहीं हुए हैं।

* विनिर्माण क्षेत्र में औपचारिक ऋण सृजन हेतु निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है :-

(i) श्रम सुधारों को लागू करना, ताकि सार्वजनिक श्रमिकों की संख्या कम हो।

(ii) विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े विनियमों - EPFO में योगदान इत्यादि को हटाने की आवश्यकता है।

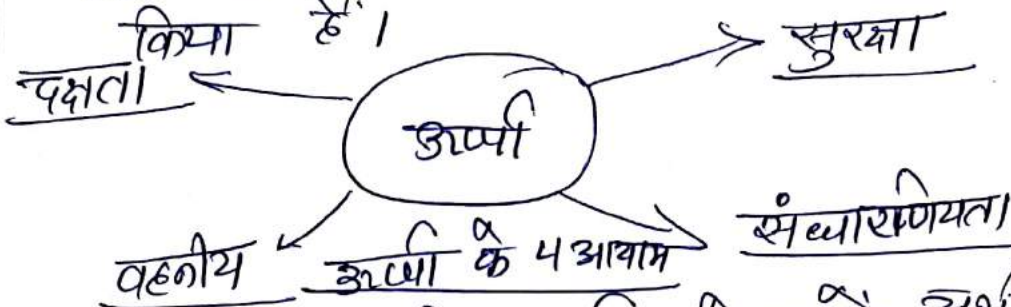
(iii) कौशल विकास तथा उन उद्योगों, जिनमें शिथिलगति सृजन करता अधिक को उत्साहन देने की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादक ऋण सृजन करने हेतु 'मैक इन इंडिया' (Make in India) 'प्रधानमंत्री योजना' (Prime Minister's Scheme) का आरंभ किया गया है।
(प्रस्ताव) लक्ष्य 2022 तक 400 मिलियन डॉलर का विनिर्माण क्षेत्र में सृजन करना है।

8. A number of far-reaching developments have taken place in the local and global energy space which have to be reflected in our own energy policy framework. Discuss.

स्थानीय और वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में कई दूरगामी घटनाएं घटित हुई हैं, जिन्हें हमारी अपनी ऊर्जा नीति के ढांचे में प्रतिबिंबित होना है। चर्चा कीजिए।

हाल ही में नीति आयोग ने भारत की ऊर्जा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया है।



भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अभी भी सर्वाधिक योगदान, कोयला (59%) का है।

हालांकि, आने वाले वर्षों में भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अधिक निवेश करेगा।

* हाल के वर्षों में स्थानीय व वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में हुए परिवर्तन:-

1) स्थानीय क्षेत्र :-

(i) भारत में सौर पैनलों, पवन ऊर्जा से जुड़े उपकरणों के इस्तेमाल में गिरावट आई है।

परमस्वल्प, इन ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश
करना, पहले से सस्ता हो गया है;

(ii) भारत ने, वायु परिवर्तन सम्मेलन
में 2035 तक 40% ऊर्जा नवीकरणीय
स्रोतों से उस कठोर लक्ष्य प्राप्त
किया है।

(iii) ग्रामीण विद्युतीकरण में तीव्रता,
पिछका लक्ष्य, 2019 तक सभी
घरों का विद्युतीकरण है।

(iv) भारत, स्मार्ट मीटरिंग, LED बल्बों,
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत
स्वच्छ ईंधन (LPG) को मुहैया कराने
संबंधी कार्य का रहा है।

- इन सभी को देखते हुए यह आवश्यक
है कि हमारी ऊर्जा नीति का लक्ष्य
प्रत्येक भारतीय को सस्ती, स्वच्छ,
दक्ष ऊर्जा उपलब्ध कराना है।

* वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य से जुड़े

बदलाव :-

(i) अमेरिका में वॉल स्ट्रीट की
उत्पादन क्षमता में बढ़े, पिछका

प्रभाव अंतराष्ट्रीय तेल कीमतों पर पड़े।

(iii) स्वच्छ ईंधन की और बढ़ती वैश्विक रुझान, जो पर्यावरण हितैषी हो।

(iii) पेट्रोल व डीजल की वजह से विद्युत से चलने वाली गाड़ियों को अपनाने में बढ़ती वैश्विक रुझान।

(iv) नए ऊर्जा स्रोतों - हाइड्रोजन इत्यादि का प्रयोग, संचार लाइनों में। उदाहरण - जर्मनी में हाइड्रोजन रेल से चलने वाली रेल।

(v) वैश्विक स्तर पर सौर टैप में आई कमी।

स्पष्ट है कि आगे वाले

भविष्य से जुड़ी ऊर्जा नीति,

नवीन ऊर्जा स्रोतों, शोध

व अडुलंधान से जुड़ी होनी चाहिए,

वित्त का लक्ष्य संधारणीय ऊर्जा

निर्माण व प्रयोग है।

9. The Indian IT-BPM (Information Technology-Business Process Management) industry is a global powerhouse today and its impact on India and the world has been unprecedented. Comment. Also, mention the challenges being faced by India's IT-BPM sector.

भारतीय IT-BPM (Information Technology-Business Process Management या सूचना प्रौद्योगिकी-व्यापार प्रबंधन) उद्योग आज एक वैश्विक शक्ति का केंद्र है और भारत एवं विश्व पर इसका प्रभाव अभूतपूर्व रहा है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, भारत के IT-BPM क्षेत्रक द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए।

भारत की पीओपी में सेवा क्षेत्र का अनुपात 50-1 से अधिक है, जिसमें सर्वाधिक योगदान IT-BPM क्षेत्र का है।

* 1994 के आर्थिक सुधारों का सर्वाधिक लाभ इस क्षेत्र को प्राप्त हुआ :-

(i) भारत विभिन्न सेवाओं के क्षेत्रों के रूप में उभरा — BPM

(ii) सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को उदारीकरण व नियोजन का सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है।
— इस क्षेत्र में FDI सर्वाधिक

तथा विदेशों से ज्ञान हस्तांतरण का लाभ प्राप्त हुआ।

(iii) भारत के विदेशी निर्यात में सर्वाधिक योगदान IT-BPM क्षेत्र के उत्पादों का है।

(iv) विभिन्न देशों की कंपनियों की शाखा, भारत में खोली गई, जिससे देश में रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं।

* हाल के वर्षों में भारत का IT-BPM क्षेत्र, विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है।

(i) व्यापारिक संरक्षणवादी नीतियों का उद्भव - अमेरिका में H1B वीजा, ब्रिटेन में Brexit जैसी नीतियों का उद्भव रोजगार पर प्रभाव डालेगा।

(ii) उच्च कौशल युक्त शैक्षणिक
सूचना में IT/BPM क्षेत्र की
असफलता के कारण, यह
क्षेत्रक कृत्रिम बुद्धिमत्ता व
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक रूप से
प्रभावित होगा।

(iii) भारत में IT क्षेत्र के उपयोग
के निर्यात में कमी आ रही है,
व हाल ही में विभिन्न कंपनियों
द्वारा गिरे राज्य के मीडिया
कर्मचारियों की हड़ती
की गई है। उदाहरण - CTS
द्वारा 90,000 लोगों की
हड़ती।

भारत का IT क्षेत्र। भारतीय
ज्ञान व आर्थिक विकास का द्योतक
है, तथा सरकार 'स्टार्ट अप इंडिया'
(अर्थ उद्योग विकास मिशन) इत्यादि द्वारा
इसे उच्च कौशल युक्त उद्योग में
परिवर्तित कर रही है।

10. An effective multi-modal logistics and transport sector will make the Indian economy more competitive. Analyse.

एक प्रभावी मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स (बहु-रूपात्मक संभरण) और परिवहन क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा। विश्लेषण कीजिए।

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स व परिवहन क्षेत्रक के अंतर्गत, एक से अधिक परिवहन के साधनों - रेल, सड़क, जल, हवाई, का प्रयोग, वस्तुओं की आपूर्ति सुखकरा हेतु किया जाता है।

• भारत में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स व परिवहन क्षेत्रक के लाभ :-

(i) यह वस्तुओं को एक स्थान से इसी स्थान तक ले - जाने में लगे जाने समय को कम करेगा।

(ii) यह परिवहन डिपेंडी सिद्ध होगा - उदाहरण सिर्फ सड़क की जगह, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, व रेलवे मालभाड़ा कोडिट का प्रयोग।

(iii) यह वस्तुओं को गुणवत्ता -

विशेषकर कृषि उत्पादों की, को
बनाए रखने का प्रयास होगा।
(iv) भारत में, परिवहन क्षेत्र, जो
मुख्य रूप से सड़क आधारित है,
विभिन्न अवसंरचना संबंधी चुनौतियों
से जूझ रहा है। इस मल्टी मॉडल
तरीके का प्रयोग, इन चुनौतियों को
दूर करने में उभारी लिये होगा।

* भारत में मल्टी मॉडल नीति (Multi-Modal Policy)
के परिवहन क्षेत्र से जुड़े अपेक्षित -

(i) मल्टी मॉडल परिवहन क्षेत्र के
अधिनियम, 1993.

(ii) अंतर्राष्ट्रीय पलमार्ग अधिनियम,
2016 के अंतर्गत पलमार्गों का
विकास।

— राष्ट्रीय पलविकास मार्ग, 5 के
अंतर्गत गंगा नदी का विकास किया
जा रहा है। (बलाहाबाद → हरिद्वार)

(iii) रेलवे द्वारा मालभाड़ा के आवागमन हेतु, फ्राइट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है।

(iv) बंदरगाहों के विकास हेतु, शांखमाला योजना, व बंदरगाहों पर नवीन तकनीक - RFID का प्रयोग

* मल्टी मॉडल लाजिस्टिक्स व परिवहन क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियाँ :

(i) पर्याप्त अवसंरचना की कमी।

(ii) भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्या।

(iii) शक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा का अभाव। (iv) बंदरगाहों या बड़े कंटेनरों से जुड़ी चुनौती।

• एडवेंस द्वारा जारी 'लाजिस्टिक्स

इंडेक्स में भारत का स्थान उच्च था, हालांकि यह विभिन्न अंतरराष्ट्रीय

मानकों को नहीं सम्मिलित करता है।

केंद्र लफा भारत में मल्टी मॉडल परिवहन के विस्तार हेतु, नई योजना शुरू करने वाली है, जिसका उभाव भविष्य के लफा होगा।

11. Climate change threatens sustainable development, impairs socio-economic development and reinforces cycles of poverty across the globe. In this context, discuss the utility of climate risk insurance as an instrument within a comprehensive climate risk management system.

जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व में संधारणीय विकास को जोखिम में डालता है, सामाजिक-आर्थिक विकास को क्षीण करता है और गरीबी के चक्र को मजबूत बनाता है। इस संदर्भ में, व्यापक जलवायु जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत एक साधन के रूप में जलवायु जोखिम बीमा की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए।

वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों से निपटने हेतु नवीन योजनाएं व नीतियां बनई जा रही हैं।

- भारत, जलवायु परिवर्तन से व्यापक रूप से प्रभावित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

* जलवायु परिवर्तन व संधारणीय विकास

(i) वैश्विक ऊष्मन के कारण १ सूखा व बाढ़ जैसी आपदाएं अधिक घटित होंगी, जिससे जनसंख्या का बड़ा भाग प्रभावित होगा।

(ii) मृदा की उत्पादकता में कमी १ जल स्रोतों विशेषकर ग्लेशियर के पिघलने के कारण, और वन वृक्षों में सतत विकास की प्रक्रिया को प्रभावित होगा।

* जलवायु परिवर्तन, सामाजिक-आर्थिक विकास व निर्धनता :-

(i) विकासशील देश व द्वितीय देश, जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित देशों।

— अभी भी इन देशों में जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग, कृषि क्षेत्र में नियोजित, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से, इन देशों के प्रभावित होने की अधिक शंका है।

(ii) जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाया इत्यादि, विकासशील देशों में अधिक विकास उत्थिता को प्रभावित होगा।

— इन देशों को अपने साधनों का एक बड़ा भाग, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु लगाना होगा।

(iii) जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक बड़ा निम्न व गरीब वर्ग को उठाना होगा।

* अलवायु ज्योखिम बीमा :-

- (i) कृषि क्षेत्र में, किसानों को अलवायु ज्योखिम बीमा, अलवायु परिवर्तन के दौर में आय सुरक्षा प्रदान कराता।
- (ii) लोगों - विशेषकर तटीय प्रदेशों में मत्स्य उद्योग इत्यादि में कार्यरत लोगों को अलवायु ज्योखिम बीमा प्रदान करना, जिससे वे इस दुर्घटना से निपटने में समर्थ हों।
- विकासशील देशों को अपने नागरिकों को अलवायु ज्योखिम बीमा कानून के संघर्ष में ज्यादा जोखिम कानून चाहिए - कलम बीमा में अलवायु ज्योखिम को शामिल करना।

12. Why are women particularly vulnerable to the impact of natural disasters? Also analyse, with adequate examples, how women can play a more effective role in disaster risk management cycle.

प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों के प्रति महिलाएं विशेष रूप से सुभेद्य क्यों होती हैं? साथ ही, समुचित उदाहरणों के साथ विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार महिलाएं आपदा जोखिम प्रबंधन चक्र में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं।

→ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपना रिपोर्ट में कहा था कि, महिलाएं प्राकृतिक आपदा से अधिक प्रभावित होती हैं, वे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक सुभेद्य हैं।

* महिलाएं प्राकृतिक आपदाओं में अधिक सुभेद्य क्यों ?

(i) पुरुषों की अपेक्षा, महिलाएं घरों में अधिक रहती हैं, कामवश आपदाओं में उनकी सत्य अधिक होती है।

उदाहरण :- सुनामी के समय, भारत में नाजपट्टनम में पुरुषों की अपेक्षा, महिलाओं की

अधिक मृत्यु हुई थी।

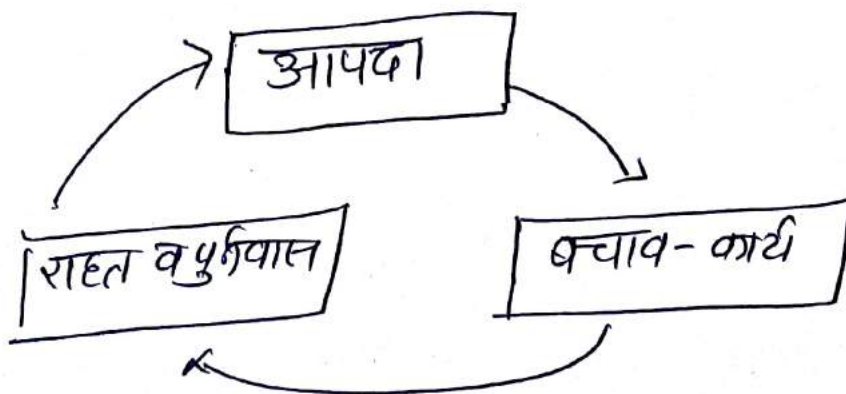
(ii) पुरुषों की अपेक्षा, महिलाएं तेरना कम जानती हैं, फलस्वरूप बाढ़ (सुगमि) में उनकी सुरक्षता अधिक है।

उदाहरण :- चेन्नई बाढ़ में महिलाएं अधिक प्रभावित।

(iii) प्राकृतिक आपदाओं का महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(iv) सूखा के कारण, इतर शहरों में ज्वला का सर्वाधिक विकास महिलाओं को होता है।

* आपदा प्रबंधन चक्र व महिलाएं



आपदा बचाव कार्य व पुनर्वास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, आपदा जोखिम को कम करने में सहायक है।

— बांग्लादेश में हर वर्ष आने वाले बाढ़ में, बड़ी मात्रा में धान-माल की हानि होती है।

हाल ही में बांग्लादेश ने, महिलाओं को तैयार सीखाने, बाढ़ के समय आवश्यक वस्तुओं व बच्चों को लेकर बचने व पुनर्वास कार्य में उन्हें सहायता राशि प्रदान करने संबंधी काम उठाए हैं, जिसके कारण वहाँ महिलाएँ आपदा जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण व सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

भारत में भी इस दिशा में पर्याप्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

13. In view of the seriousness of heat waves and its consequences, greater attention is required for dealing with it as a natural disaster. Analyse in the context of recent developments and the actions taken by relevant government bodies.

हीट वेव (ग्रीष्म लहर) और उसके परिणामों की गंभीरता के आलोक में, एक प्राकृतिक आपदा के रूप में इससे निपटने हेतु अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हाल के घटनाक्रमों और संबद्ध सरकारी निकायों द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।

हाल के वर्षों में भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान हीट वेव की गंभीर समस्या बम गया है।

* IMD के अनुसार, जब किसी क्षेत्र का तापमान 40°C हो, तथा यह लगातार 3-5 दिनों तक रहे तो इसे हीट वेव घोषित करना चाहिए।

- किसी क्षेत्र का तापमान 45°C रहे पर, तुरंत हीट वेव की घोषणा की जानी चाहिए।

* हीट वेव : परिणाम

(i) हाल के वर्षों में अलवायु परिवर्तन व ग्लोबल वार्मिंग के कारण, भारत में ग्रीष्म

ग्रेट (मार्च-जून) का तापमान
अधिकतर शहरों में 40°C से
अधिक रह रहा है।

(ii) ग्राम लहर के कारण, शहर
में पानी की कमी, सिर दर्द,
व यहाँ तक की मृत्यु भी हो
जाती है।

हालिया वर्षों में ग्राम लहर के
कारण होने वाली मृत्यु की
संख्या में एहड़ें हुई हैं।

• चूंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या
ग्राम लहर से प्रभावित होती है,
आवश्यकता है कि इस संबंध
में पर्याप्त जागरूकता फैलाई जाए।

(i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(NDMA) द्वारा ग्राम लहर के बारे में
बचने हेतु उपाय ज्ञान वाले
कार्डों को प्रसारित करने की
आवश्यकता है।

(ii) अधिक घम दिन में, लोगों को घरे के अंदर रहने व बाहर न निकलने संबंधी निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

~~संबंध~~ * शीघ्र लहर के संबंध में उठाए गए कदम :-

(i) IMD का, तापमान का पूर्वानुमान जारी करना।

(ii) NDMA का, शीघ्र लहर से निपटने हेतु, दिशा-निर्देश जारी किया जाना।

भविष्य में उन्मुखी वॉरिंग के कारण, शीघ्र लहर की घटना में और हाई होगी, जिससे निपटने हेतु होस तंत्र व उक्तिमा अपनाने की आवश्यकता है।

14. While genome editing offers immense potential benefits in the area of healthcare, there are a lot of apprehensions regarding its use. Discuss.

जहां, जीनोम एडिटिंग स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ की संभावना प्रस्तुत करता है, वहीं इसके उपयोग के संबंध में काफी आशंकाएं भी मौजूद हैं। चर्चा कीजिए।

हानि के खतरों में जीनोम एडिटिंग,
काफी चर्चा में है।

• जीनोम एडिटिंग के अंतर्गत, किसी
व्यक्ति / बच्चों के जीनोम में
परिवर्तन किया जाता है।

- जीन, मनुष्य के DNA में
पाए जाने वाले आनुवंशिक कारक
हैं, जो व्यक्ति की विभिन्न आनुवंशिक
गुणों को भंडारित करते हैं।

* जीनोम एडिटिंग :-

(i) वैशानिक, जीनोम एडिटिंग
की सहायता से, किसी व्यक्ति
में पाए जाने वाले, आनुवंशिक
रोगों - थेलासीमिया के वाहक
जीनों को निकाल पाएंगे।

— प्पनीम उडिडिंग की लहायत से, आनुवांशिक रोगों का डलाप संभव डेगा ।

(ii) प्पनीम उडिडिंग से किसी व्यक्त की कमता — कुडि केशल में भी लुडे संभव डेगी ।

(iii) प्पनीम उडिडिंग काश कैंसर पाडक प्पनीना की पहचान कर, उडे परिवर्तन। बाहर निकलना प्प सकेगा, कलस्वरुप यह कैंसर का डलाप भी भविष्य में मुडेया काडगा।

(iv) पशुओं — पुधारु कुशुओं की प्पनीना में उडिडिंग काश, डीधकु दुध उत्पादन संभव डेगा ।

(v) पौधों व कसलों की उत्पादन में लुडे डेगी तथा वे कमवाडु परिवर्तन से विपडे में लकम डेगे ।

* पीनोम प्रतिष्ठान :-

- (i) डिप्टी डिप्टी, जिसके सभी विशेषताओं का पीनोम कला संभव होगा।
- (ii) भाविष्य में, मनुष्य आधुनिक कार्यों का नहीं, बल्कि पीनोम प्रतिष्ठान द्वारा नियंत्रित होगा।
- (iii) इस तकनीक का उपयोग, कार्य करने में है कि पीनोम प्रतिष्ठान उन्हें विभिन्न संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं वहीं इसके उपयोग से पुड़ी नैतिक नियंत्रण भी विद्यमान है।

15. Discuss various ways in which supercomputers have benefitted mankind over the years. Also enumerate the objectives of the National Supercomputing Mission and the mechanism for its implementation.

उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिसके माध्यम से विगत वर्षों में सुपर कंप्यूटरों ने मानव जाति को लाभान्वित किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के उद्देश्यों और इसके कार्यान्वयन के तंत्र को भी सूचीबद्ध कीजिए।

→ सुपर कंप्यूटर, इन कंप्यूटरों को कहते हैं, पिछली कंप्यूटरों की क्षमता बहुत अधिक होती है। सुपर कंप्यूटर, चंद्र सैल में बहुत बड़ी क्षमता के साथ काम करते हैं।

* सुपर कंप्यूटर : प्रयोग

- (i) मानव सुवीरुमान-सटिक होना।
- (ii) चक्रवात से जुड़ी सुवीरुमानों के कारण, वर्षों हवा लीगों की ध्यान बची है।
- (iii) बिग डाटा सुनॉलिटिक्स में।

- (iv) अंतरिक्ष विज्ञान में ।
(v) चिकित्सा क्षेत्र में - नई दवाओं की खोज ।

* राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन

- केंद्र सरकार द्वारा 45,000 करोड़ रुपये राशि की, सुपरकंप्यूटिंग मिशन की घोषणा की गई है ।

— यह मिशन 7 वर्षों के लिए है ।

* मिशन का उद्देश्य

- सुपरकंप्यूटर युक्त देशों की सूची में भारत को अग्रणी स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना ।

* मिशन : मुख्य बिंदु

- (i) भारत में सुपरकंप्यूटर्स के विकास को प्रोत्साहन देना ।
- (ii) वैज्ञानिकों व शोधकर्तियों को सुपरकंप्यूटर उपलब्ध कराना उनकी समता में छूट देना ।
- (iii) देश के अग्रणी संस्थानों को सुपरकंप्यूटर की गिड उपलब्ध कराना जोड़ना, व एक इतने नेटवर्क की स्थापना करना ।
- एक के वर्षों में भारत सुपरकंप्यूटर की दौड़ में पीछे रह गया है, तथा चीन इस क्षेत्र में अग्रणी हो गया है ।
- आवश्यकता है कि यह मिशन अपने उद्देश्य में सफल हो, इसके लिए सी-ईओ जैसे लेखकों को प्रोत्साहित है ।

16. Widely seen as a disruption for the traditional banking and financial institutions, cryptocurrencies have gained significant traction lately, at the same time creating a regulatory nightmare for regulators across the globe. Discuss.

पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के लिए व्यापक रूप से व्यवधान के रूप में देखी जाने वाली, साथ ही विश्व भर में नियामकों के लिए एक नियामकीय दुःस्वप्न का निर्माण करने वाली, क्रिप्टोकॉरेंसी ने हाल ही में महत्वपूर्ण पकड़ स्थापित की है। चर्चा कीजिए।

क्रिप्टोकॉरेंसी, एक वर्चुअल कॉरेंसी है, जो, इनफ्रिक्शन हेतु क्रिप्टो तकनीक का प्रयोग करती है।
उदाहरण :- बिटकॉइन।

* क्रिप्टोकॉरेंसी : तकनीक
A → B ब्लॉकचेन



— यह पीयर टू पीयर, धन हस्तांतरण हेतु, ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करती है, जिसके अंतर्गत दो व्यक्तियों के मध्य वित्तीय लेन-देन हेतु, किसी तीसरे / मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है,

• ब्लॉकचेन, एक सार्वजनिक बहिष्कृतता (Public ledger) है, जिसके अंतर्गत किसी नेटवर्क के अंतर्गत कुछ लक्ष्मी वित्तीय लेन-देन की सूची सम्मिलित होती है।

* क्रिप्टोकॉसी : लाभ

- (i) व्यक्ति की निष्पत्ता बनी रखी है
- (ii) वित्तीय लेन-देन हेतु, किसी मध्यस्थ-बैंक की आवश्यकता नहीं है।
- (iii) धन हस्तांतरण से जुड़ी लक्ष्मी व्यापकता (सार्वजनिक रूप से उपलब्ध), जिस नेटवर्क के लक्ष्मी मशीनों द्वारा सत्यापित किया गया।
— कमस्वरूप चौखाथड़ी या हेलाफी की संभावना नहीं है।
- (iv) विभिन्न देशों की कुल से जुड़े अंतर-पड़स से उभाकित नहीं होती है।

- * क्रिटीकोली : एन। -
- (i) यह किसी राष्ट्रीय बैंक द्वारा समर्थित नहीं है;
- (ii) इसका प्रयोग व्यवस्थापकों के विशेषण व साक्षर लोगों के पौष्टिक किया जाता है;
- उदाहरण :- Rousemware अर्थ

एन। ही में, भारत में विपुलीकरण परचा, क्रिटीकोली की मांग में बढ़ि हुई है।

- केंद्र द्वारा क्रिटीकोली के अर्थ पर अंतरातीय पोषक का ठाठ किया गया था, पोषक के अर्थ सिफारिश में क्रिटीकोली के विनियमन हेतु क्रिटीकोली के अर्थ की सिफारिश की है।

क्रिटीकोली, अविषय की कोली साहित हो सकती है, जिसे देखते हुए वल शिक्षा के पर्याप्त उपाय को भी आवश्यक है।

17. An internationally-binding agreement to strengthen the Outer Space Treaty of 1967 is both desirable and increasingly a necessity. Analyse in view of the traditional and emerging challenges in this arena.

1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि को मजबूत बनाने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय बाध्यकारी समझौता वांछनीय और साथ ही एक आवश्यकता दोनों है। इस क्षेत्र में पारंपरिक और उभरती हुई चुनौतियों के आलोक में विश्लेषण कीजिए।

बाह्य अंतरिक्ष संधि के लग ही में
50 वर्ष हो चुके हैं।

- 1957 में रूस द्वारा स्युतनिक
उपग्रह भेजे जाने व शीत युद्ध
का चपेट में अंतरिक्ष के आगे
के पर्यटन, संयुक्त राष्ट्र लैंग्वेज
एक समिति का गठन किया।
- इस समिति द्वारा की गई
सिफारिशों का परिणाम 9 बाह्य
अंतरिक्ष संधि के रूप में, 1967
में सामने आया।

* बाह्य अंतरिक्ष संधि : मुख्य
बिंदु :-

- (i) अंतरिक्ष का प्रयोग सभी
देशों द्वारा शांतिपूर्ण

उद्देश्यों हेतु किया जाएगा।

(ii) इस संधि की धारा IV के

अनुसार -

कोई भी देश सैन्य उद्देश्यों हेतु वायु अंतरिक्ष का उपयोग नहीं करेगा।

(iii) चंद्रमा व अन्य अंतरिक्षीय पिंडों का प्रयोग, अन्वेषण हेतु किया जाएगा।

इस संधि के कारण ही, वायु अंतरिक्ष का उपयोग खांतिपूर्ण ढंग से होना संभव हो पाया है।

* हाल के वर्षों में मिल रही नवीन चुनौतियों में प्रमुख हैं :-

(i) अंतरिक्ष अन्वेषण व पर्यटन में निष्पी केंद्र की भूमिका स्पेस X जो

उदाहरण :-

अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देगा।

(ii) क्वांटम तकनीक का प्रयोग, विशेषकर, उपग्रहों से प्राप्त सूचना में, क्वांटम कम्युनिकेशन तकनीक का प्रयोग।

उदाहरण :- चीन द्वारा क्षमिका प्रयोग।

आगे वाले समय की चुनौतियों को देखते हुए यह आवश्यक होगा कि, बाह्य अंतरिक्ष समझौते के तहत तत्वों को सम्मिलित किया जाए।

18. Even after nearly 60 years in existence, AFSPA remains at the centre of debates with respect to countering violent insurgencies, role of the states and local communities. Discuss.

अस्तित्व में आने के लगभग 60 वर्षों के बाद भी, हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने और राज्यों व स्थानीय समुदायों की भूमिका को लेकर AFSPA वाद-विवाद के केंद्र में बना हुआ है। चर्चा कीजिए।

केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित, AFSPA कानून का प्रयोग, जम्मू-कश्मीर व उत्तर-पूर्वी राज्यों - मणिपुर, नागालैंड में, अकाशवादी व आतंकवादी तत्वों से निपटने हेतु किया जाता है।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने AFSPA कानून को लेकर प्रश्नचिह्न लगाए हैं।

* AFSPA कानून : बिंदु :-

(i) उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में यह कानून प्रशासकों को

विशेषाधिकार प्रदान करता है :-
सच, व्यक्ति को संकेत के आधार पर गिरफ्तार करना।

(ii) AFSPA के अंतर्गत किसी व्यक्ति को मारने संबंधी प्रावधान को लेकर सर्वाधिक वाद-विवाद है।

(iii) AFSPA काबूग सशस्त्र बलों को मानवाधिकार आयोग व न्यायालयों में उनके कृत्यों के संबंध में उन्मुक्ति प्रदान करता है।

हाल के दिनों में मानवाधिकार आयोग ने, AFSPA काबूग में पर्याप्त सुशोधन करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

- AFSPA काबूग के अंतर्गत मारे गए लोगों के संबंध में जांच का आदेश, सैन्य कमिटी को इस हेतु देषी ठहराना, केंद्र लकाना के इस संबंध में उन्मुक्ति के अंतर्गत रिपोर्ट उप कराना, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है, जो

मांगवाधिका (आयोग) ने सुझाए हैं।

• AFSPA का बहाना = विपदा :-

(i) यह भारत को लोक-कल्याण
-कारी राज्य की ओर पुलित
राज्य में परिवर्तित करता है।

(ii) AFSPA के अंतर्गत कई बार
निर्दोष लोगों की जान गई है।
उदाहरण :- माचिल एनकाउंटर।

(iii) AFSPA का बहाना, राज्यों व
सैन्य बलों के मध्य अविश्वास
को और बढ़ा रहा है।

(iv) 'मांगवाधिकाओं' का उन्मूलन, जैसे
का बहाना न्याय।

आवश्यकता है कि

AFSPA का बहाना में सरकार, विधि
कर्मियों पर पर्याप्त कार्यवाही करें।

19. Analyse the challenges and opportunities inherent in the push for indigenisation of defence production in India. Also, identify the measures through which indigenous manufacturing of defence equipments is being encouraged by the Government.

भारत में रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण की दिशा में निहित चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, उन उपायों की भी पहचान कीजिए जिनके माध्यम से रक्षा उपकरणों का स्वदेशी निर्माण सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने, नवीन रक्षा खरीद योजना की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य, रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन देना है।

* भारत में रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण में निहित चुनौतियां:-

- (i) पर्याप्त अनुसंधान व शोध का अभाव।
- (ii) नवीन रक्षा तकनीकों के संबंध में आने-भिन्नता।
- (iii) विपरीत क्षेत्र को उस क्षेत्र में प्रोत्साहन देने हेतु, अवसरों व नीतियों का अभाव।

(iv) भारत, रक्षा उपकरणों का वैश्विक स्तर या सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन उसके स्वदेश में रक्षा उपकरणों के विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया है;

* रक्षा उत्पादन स्वदेशीकरण : अवसर

- (i) रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण से, भारत आत्मनिर्भर लेन्य व्यक्ति के रूप में विकसित होगा। यह मिक इन इंडिया को प्रोत्साहन देगा।
- (ii) भारत के विदेशी मुद्रा व्यय में कमी आएगी।
- (iv) इस क्षेत्र में पीपीपी जैसे - प्लांटों व FDI के व्यापक निवेशकों के प्रोत्साहन दिए जायेंगे, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे।

* रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम।

(i) नवीन रक्षा खरीद नीति, 2017 की घोषणा।

(ii) रक्षा उपकरण उत्पादन में FDI को अनुमति।

(iii) DRDO व निष्पक्ष क्षेत्र सिविल उपकरण विकसित करेंगे।

20. India's ability to pursue a clear-cut strategic vision depends on its ability to improve institutional cooperation and coordination between the armed forces and civilian bureaucracy. Discuss.

भारत द्वारा एक सुस्पष्ट रणनीतिक दृष्टि का अनुसरण करने की क्षमता वस्तुतः सशस्त्र बलों और सिविल नौकरशाही के बीच संस्थागत सहयोग और समन्वय में सुधार करने की क्षमता पर निर्भर करती है। चर्चा कीजिए।

भारत में, सशस्त्र बलों व सिविल नौकरशाही के मध्य सहयोग व समन्वय में सुधार आवश्यक है।

* सशस्त्र बलों व सिविल नौकरशाही के मध्य विवाद :-

(i) सिविल नौकरशाही, सशस्त्र बलों की तीन दशकों से जारी पग बैंक-कटौत योजना की मांग को लागू करने के लिए अग्रिम रूढ़ि रही है।

(ii) रक्षा बजटों में विशेषकर, सशस्त्र बलों के वेतन मांग

से जुड़े व्यक्तियों को लागू करने
में इसका सिविल नौकरवाही
भाग - कगि कती रही है।

(iii) सिविल लेवकों का अभिवात
- कीय दृष्टिकोण भी इस
असहयोग का प्रमुख कारण है।

हालांकि हाल ही में सरकार बकों
के लिए 7% वेतन मांग की
लिफ्टशिओ व OROP की नीति
को लागू करने में, केंद्र सरकार
में तत्पत्ता दिखई है।

